



भारत का दाता पत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—सुप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मा. 315] नई विलासी, मंगलवार, बूँद 24, 1986/प्राप्ति 3, 1908
No. 315] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1986/ASADHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती हैं जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Pagings is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंडालम् (राजस्व विभाग)

नई विल्ली, 24 जून, 1986

प्रधिसुचनाएँ

सं. 368/86-सीमाण स्क

सा. का. नि. 903 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-गुल्क भविभित्ति, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधरा (1) द्वारा ब्रह्मगितयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिकृतना म. 276/85-सीमा-गुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1985 में निम्नलिखित और संयोधन करती है, प्रथमतः—

रक्षत प्रधिसूचना में प्रारंभिक पैरा में, अंक (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित अंक रखें जाएंगे, प्रधार्त :—

(ii) विनिर्माता सीभा-ग्रुप्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के समक्ष इन भाषणों का साक्षय पेश करता है कि उक्त पोलिएस्टर फाइबर, भारत के भाष्यार पर उक्त पोलिएस्टर फाइबर के लालीत व्यतिरिक्त

से अधिक किन्तु सत्तर प्रतिशत से कम वाले कम कीमत के कपड़ों के विनिर्माण के लिए—

(क) हैंडलूम पर चुने गए फैक्रिक की दला में, हृषकरथा विकास आपूर्त द्वारा :

(क) भारतीय फैलिकों की दशा में, वस्तु आयुक्त और पूर्णि और वस्तु महानय के संयुक्त सचिव की रैंक से वर्तमान किसी अधिकारी द्वारा, सम्पूर्ण रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के ध्वनीन प्रयोग के लिए आशयित है :

(iii) विनियोगी, ऐसी घटनाएँ के भीतर जो सीमांशुलक सहायक विनियोगी ऐसी विनियोगी विनियोगी हों—

(क) हैंडलूम पर बुने गए फैटिक की दशा में, राज्य सरकार से अपने अधिकारियों के लिए सामाजिक निवेशक से ।

(प) एवं वैशिकों की वस्ता में, वस्तु आयक्त से;

इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि फाइबर का प्रयोग उच्चपूर्ण प्रयोजन के लिए किया गया है।"

फा. सं. 357/16/86-दो अर दू]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th June, 1986

NOTIFICATIONS

No. 368/86-CUSTOMS

G.S.R. 903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 276/85-Customs dated the 28th August, 1985, namely:—

In the said notification in the opening paragraph, for clauses (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said polyester fibre is intended for use under a programme duly approved,—

(a) in the case of fabrics woven on hand-looms, by the Development Commissioner for Handlooms;

(b) in the case of other fabrics, by the Textile Commissioner and an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Supply and Textiles,

for the manufacture of low price fabrics containing more than 40 per cent. but less than 70 per cent by weight of the said polyester fibre;

(iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate,—

(a) in the case of fabrics woven on handlooms from the Director in charge of textiles and handlooms in the Government of a State;

(b) in the case of other fabrics, from the Textile Commissioner,

to the effect that the said polyester fibre has been used for the aforesaid purpose.”

[F. No. 357/16/86-TRU]

सं. 357/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवत्त शान्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

प्रधिसूचना सं. 191/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, प्रथात्:—

उक्त प्रधिसूचना के प्रारंभिक पंरा में, छंड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित छंड रखे जाएंगे, प्रथात्:—

“(ii) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस भाष्य का साथ्य पेश करता है कि उक्त पोलिएस्टर फाइबर, भार के आधार पर उक्त पोलिएस्टर फाइबर के चालीस प्रतिशत से अधिक किन्तु मत्तर प्रतिशत से कम वा ते कम कीमत के कपड़ों के विनिर्माण के लिए,—

(क) हैंडलूम पर बुने गये फैब्रिक की दशा में, हथकरथा विकास आयुक्त द्वारा;

(ख) अन्य फैब्रिक की दशा में, वस्त्र आयुक्त और वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव की रैंक से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा,

सम्पूर्ण से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन प्रयोग के लिए प्राप्तियत है;

(iii) विनिर्माता, ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर इस निम्न विहित करे,—

(क) हैंडलूम पर बुने गये फैब्रिक की दशा में, राज्य सरकार के वस्त्र और हथकरथा के भार साधक निदेशक से;

(ख) अन्य फैब्रिकों की दशा में, वस्त्र आयुक्त से, इस भाष्य का प्रमाणपत्र पेश करता है कि फाइबर का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया गया है।”

[फा. सं. 357/16/86-दी भार. यू.]
बी. श्रीधर, उप-सचिव

No. 357/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 904(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 191/85-CE dated the 28th August, 1985, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, for clauses (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(ii) the manufacturer produces evidence to the Assistant Collector of Central Excises to the effect that the said polyester fibre is intended for use under a programme duly approved,—

(a) in the case of fabrics woven on handlooms, by the Development Commissioner for Handlooms;

(b) in the case of other fabrics, by the Textile Commissioner and an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Supply and Textiles,

for the manufacture of low price fabrics containing more than 40 per cent but less than 70 per cent by weight of the said polyester fibre;

(iii) the manufacturer shall, within such period as the Assistant Collector of Central Excise may specify in this behalf, produce a certificate,—

(a) in the case of fabrics woven on hand- looms, from the Director in charge of textiles and handlooms in the Government of a State;

(b) in the case of other fabrics, from the Textile Commissioner,

to the effect that the said polyester fibre has been used for the aforesaid purpose.”.

[F. No. 357/16/86-TRU]

V. SRIDHAR, Dy. Secy.

